जी. एस. सिंघवी *और टी. एच. बी. चलपति के समक्ष*

सुरेश कुमार और एक और,-याचिकाकर्ता।

बनाम

स्टेट ऑप हरियाणा और अन्य,-उत्तरदाता,

C.W.P. No. 6226 *of* 1995

9 अक्टूबर, 1995

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973-धारा *9* (3)-हरियाणा *नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1994-भारत* का *संविधान, 1950-73वां संशोधन-अनुच्छेद* 243-आर-नगरपालिका *आयुक्त के* पद *के* लिए *नामांकन-सरकार को नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले* व्यक्तियों *में से 3 व्यक्तियों को नगरपालिका समिति में नामित करने का अधिकार है-सामग्री की अनुपस्थिति में में नामांकित व्यक्ति धारा 9 (3) की शर्तों को* पूरा *करते हैं।नामांकन रद्द किए जाने योग्य हैं।*

अभिनिर्धारित किया कि जब तक कोई व्यक्ति नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव नहीं रखता है, सरकार अधिनियम की खंड 9 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करके उसे नामित नहीं कर सकती है।

(पैरा 11)

आगे माना गया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के दायरे को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 40 वर्षों में, इस वाक्यांश ने एक निश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया है और

अब यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के सभी विधायी और कार्यकारी कार्यों के संबंध में और सरकार या किसी व्यक्ति में निहित पूर्ण शक्ति की अवधारणा को क्रमिक रूप से नकारात्मक कर दिया गया है।

(पैरा 12)

इसके अलावा, यह माना गया कि शक्ति सरकार में निहित है। खंड (i) के तहत तीन व्यक्तियों को नामांकित करना पूर्ण नहीं है बल्कि नामांकित किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है। इसलिए, यदि यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया है जिसके पास नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव नहीं है, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग मनमानी और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा। .

(पैरा 19)

इसके अलावा, यह माना गया कि निजी उत्तरदाताओं में से किसी को भी नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान नहीं है और न ही उनके पास नगरपालिका प्रशासन में कोई अनुभव है और अपनी ओर से, सरकार ने उन्हें नगरपालिका समितियों में नामांकित करते समय अपने दिमाग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों का कर्तव्य मुख्यमंत्री को कानून की आवश्यकताओं के साथ-साथ नामांकित किए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव के बारे में सिखाना है, वे अपने कर्तव्य में पूरी तरह विफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों को नामांकित किया गया जो कानून की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे।

(पैरा 20)

वाई.के. शर्मा - याचिकाकर्ताओं के वकील

एस. दीनारपुर - वकील प्रतिवादि संख्या 3 से 5 के लिए।

आर.एन. कैना, डीएजी, हरियाणा - दोनों याचिकाओं में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए

निर्णय

न्यायमूर्ति जी. *एस. सिंघवी*

1) इन दोनों याचिकाओं में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 9(3) के तहत नगरपालिका समिति, बुराई, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर और नगरपालिका समिति, पुन्हाना जिला गुड़गांव में निजी प्रतिवादियों के नामांकन को चुनौती दी गई है। संक्षेप में, अधिनियम)। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं 3 से 5 (1995 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 6226 में) और सी.डब्ल्यू.पी. में प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन को रद्द करने की प्रार्थना की है। 1985 का क्रमांक 3874.

2) C.W.P. No. 6226 of 1995 सुरेश कुमार और नूर मोहम पागल द्वारा दायर की गई है जो नगरपालिका समिति, बुरिया, तहसील जगत हरि, जिला यमुनानगर के निवासी और मतदाता हैं। नगरपालिका समिति, बुरिया के चुनाव 28.1.1994 को हुए और कुल मिलाकर ग्यारह व्यक्तियों को नगर आयुक्त के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। उनमें से चार महिला उम्मीदवार हैं और सात पुरुष उम्मीदवार हैं जो वार्ड नंबर 2 से सामान्य श्रेणी के चयन के लिए उत्सुक हैं, लेकिन एक श्री असगर अली से हार गए। चुनाव में अपनी हार

के लगभग दो महीने बाद, अधिनियम की धारा 9(3) के तहत सरकार में निहित शक्तियों के कथित प्रयोग में जारी सरकारी अधिसूचना संख्या 20.2.1995 के तहत प्रतिवादी नंबर 3 को नगरपालिका समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।. याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 3 के साथ-साथ प्रतिवादी 4 और 5 के नामांकन को इस आधार पर चुनौती दी है कि उनमें से किसी के पास नगरपालिका प्रशासन में कोई विशेष ज्ञान या अनुभव नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3, केवल प्राइमरी पास है और उसे उर्दू और हिंदी भाषाओं का कुछ ज्ञान है। उत्तरदाताओं 4 और 5 के बारे में यह भी कहा गया है कि वे केवल 6वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और उनके पास नगरपालिका प्रशासन में कोई विशेष ज्ञान या अनुभव है और इस प्रकार, उनमें से किसी को भी अधिनियम की धारा 9(3) के तहत सरकार द्वारा नामित नहीं किया जा सकता है।

3) रिट याचिका का प्रतिवादि संख्या 1 और 2 के साथ-साथ प्रतिवादी 3 से 5 ने विरोध किया है। अपने जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने अनुरोध किया है कि अधिनियम की धारा 9(3) को हरियाणा नगर निगम के माध्यम से अधिनियम में जोड़ा गया है। संशोधन अधिनियम, 1994, और इस प्रावधान के मद्देनजर, सरकार को नगर पालिका समितियों में सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। प्रतिवादी के अनुसार, इन सदस्यों को नगरपालिका समिति की कार्यवाही में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पास उनके नामांकन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। जवाब के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि सभी तीन नामांकित सदस्यों (प्रतिवादी 3 से 5) ने नगरपालिका चुनाव लड़ा है और इस तरह उनके पास नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव था।

4) अपने उत्तर में, प्रतिवादी 3 से 5 ने याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने दलील दी है कि नगर निगम चुनाव में हारे हुए व्यक्ति के नामांकन पर कोई रोक नहीं है। उत्तरदाताओं के अनुसार, सरकार को अधिनियम की धारा 9(3) के तहत सदस्यों को नामित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है और लागू अधिसूचना में कोई संवैधानिक कमजोरी नहीं है।

5) C.W.P. No. 3874 of 1995 नगर पालिका पुन्हाना निवासी ओम प्रकाश ने दायर की है। दिसंबर, 1994 में हुए चुनावों में, इस नगरपालिका समिति के लिए कुल मिलाकर ग्यारह व्यक्ति चुने गए। प्रतिवादी संख्या 3 ने चुनाव लड़ा लेकिन वह हार गई। दिनांक 20.2.1995 की अधिसूचना द्वारा उन्हें नगरपालिका समिति में भी नामांकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन को चुनौती देने के आधार सी.डब्ल्यू.पी. में निर्धारित आधारों के समान हैं। क्रमांक 6226/1995 और उत्तरदाताओं द्वारा दायर उत्तर भी उसी तर्ज पर है। इसलिए, इस याचिका में उठाए गए आधारों का विस्तृत संदर्भ और उत्तर आवश्यक नहीं है।

6) एकमात्र बिंदु जिस पर पार्टियों के वकील द्वारा तर्क दिए गए हैं और जो न्यायालय द्वारा निर्धारण की मांग करता है, उसमें दो तथ्य हैं; पहला यह है कि क्या सरकार के पास अधिनियम की धारा 9(3) के तहत नगरपालिका समितियों में सदस्यों को नामित करने की पूर्ण शक्ति है और दूसरा यह है कि क्या निजी उत्तरदाताओं का नामांकन दूषित है क्योंकि उनमें से किसी के पास नगरपालिका प्रशासन में अनुभव का विशेष ज्ञान नहीं है।

7) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नगरपालिका समितियों में सदस्यों को नामांकित करने के लिए सरकार को प्रदत्त शक्तियां न तो पूर्ण हैं और न ही बेलगाम हैं, बल्कि इस शर्त के साथ जुड़ी हुई हैं कि नगरपालिका समितियों में नामांकित

व्यक्तियों को नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। और, इसलिए, जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि नामांकित व्यक्तियों के पास नगरपालिका प्रशासन में अनुभव का विशेष ज्ञान है, सरकार की कार्रवाई ख़राब होने के लिए उत्तरदायी है।

8) दूसरी ओर, दोनों याचिकाओं में उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता, हरियाणा और निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि धारा 9(3) के तहत सदस्यों को नामित करने की सरकार की शक्ति है। सरकार के मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

9) संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से भाग IX और IX-A को जोड़ा गया है। भाग IX 'पंचायत' से संबंधित है और भाग IX-A 'नगर पालिकाओं' से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 243-आर नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

243-द . नगर पालिकाओं की संरचना:- 1). खंड (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी। नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, --

1 संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (1-6-1993 से) अंतःस्थापित।

(क) नगरपालिका में,--

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का;

(ii) लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं;

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(iv) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा :

परंतु पैरा (त) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा ;

(ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा।

10)संविधान के अनुच्छेद 243-आर के अनुपालन में, अधिनियम को हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित किया गया है, और अधिनियम में लाए गए संशोधनों में से एक धारा 9 में है। धारा 9 जैसा कि 1994 से पहले था। संशोधन और 1994 के संशोधनों के बाद की स्थिति इस प्रकार है:-

"धारा 9 - समितियों का गठन - प्रत्येक नगर पालिका के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कम से कम सात निर्वाचित सदस्य होंगे जो राज्य सरकार इस संबंध में तय कर सकती है:

बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित संख्या में नामांकित सदस्य शामिल नहीं होंगे।

(3) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों के अलावा, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को नगर पालिका के सदस्यों के रूप में नामित करेगी: -

(i) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन से अधिक व्यक्ति नहीं;

(ii) लोक सभा और राज्य की विधान सभा के सदस्य, उन घटक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है; और

(iii) राज्य परिषद के सदस्य, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत;

बशर्ते कि उपरोक्त खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

बशर्ते कि नगरपालिका परिषद के मामले में कार्यकारी अधिकारी और नगरपालिका समिति के मामले में सचिव को नगरपालिका की सभी बैठकों में भाग लेने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उनमें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ।"

11)उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि हरियाणा विधानमंडल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आर में शामिल संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी कर दिया है, अधिनियम की धारा 9(3) सरकार को तीन व्यक्तियों को नामांकित करने का आदेश देती है। नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव होना। इससे पता चलता है कि जब तक किसी व्यक्ति के पास नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव न हो, सरकार अधिनियम की धारा 9(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करके उसे नामांकित नहीं कर सकती है। यह तथ्य कि क़ानून अधिनियम की धारा 9(3) के तहत नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता निर्दिष्ट करता है, विद्वान उप महाधिवक्ता और निजी उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान वकील के तर्क को नकार देता है कि सरकार के पास पूर्ण अधिकार है। अधिनियम की धारा 9(3) के तहत किसी भी व्यक्ति को नामांकित करने की शक्ति।

12)इस तथ्य के अलावा कि अधिनियम की धारा 9(3) में उन व्यक्तियों की योग्यता शामिल है जिन्हें सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है, हमारी सुविचारित राय है कि पूर्ण शक्ति का तर्क जैसा कि विद्वान वकील द्वारा आगे बढ़ाया गया है उत्तरदाता अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय को केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है, मौलिक अधिकारों को लागू करने और अन्य उद्देश्यों के लिए उचित रिट जारी करने की अधिक शक्ति उच्च न्यायालयों के पास निहित है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के दायरे और दायरे को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 40 वर्षों में, इस वाक्यांश ने एक निश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया है और अब यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग बार-बार किया जा सकता है। राज्य के सभी विधायी और कार्यकारी कार्यों का सम्मान और

सरकार या किसी व्यक्ति में निहित पूर्ण शक्ति की अवधारणा को क्रमिक रूप से नकारात्मक कर दिया गया है।

13)भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति भी न्यायालयों की जांच के अंतर्गत आ गई थी।

14)राजस्थान राज्य और भारत संघ एवं अन्य[1], सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा कि "सिर्फ इसलिए कि किसी प्रश्न का राजनीतिक महत्व है, यह अपने आप में कोई आधार नहीं है कि अगर अदालत संवैधानिक निर्धारण का मुद्दा उठाती है तो उसे संविधान के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने से क्यों पीछे हटना चाहिए..." ...केवल इसलिए कि प्रश्न का राजनीतिक रंग है, न्यायालय निराशा में हाथ नहीं मोड़ सकता और "न्यायिक हाथ खाली" नहीं कर सकता। न्यायालय ने आगे कहा; "लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण है या आधारित है पूरी तरह से अप्रासंगिक और अप्रासंगिक आधार पर, न्यायालय के पास इसकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा। यह संकीर्ण न्यूनतम क्षेत्र है जिसमें अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। खंड (i) न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसके अलावा, यह राष्ट्रपति की संतुष्टि को चुनौती देने के लिए न्यायालय पर निर्भर नहीं रह सकता है कि उस खंड में जिस स्थिति पर विचार किया गया है मौजूद।"

15)मामले की फिर से एस.आर. बोम-माई और अन्य में नौ-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा जांच की गई है। वी भारत संघ एवं अन्य, 1994(1) एस.सी.सी. 1 और यह सर्वसम्मति से माना

[1] 1977(3) एस.सी.सी. 592,

गया है कि न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है। अपने फैसले में, रामास्वामी, जे. ने कहा:-

"न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों का संवैधानिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वे न्यायिक समीक्षा को विवेक पर प्रहरी के रूप में लागू करें। न्यायिक समीक्षा का संबंध निर्णय के गुणों से नहीं है, बल्कि निर्णय के तरीके से है। निर्णय लिया गया।"

रेमास्वामी, जे. ने आगे कहा:-

"न्यायिक समीक्षा को न्यायालय द्वारा न्यायसंगतता से अलग किया जाना चाहिए। दोनों अवधारणाएं पर्यायवाची नहीं हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक घटक शक्ति है और इसे व्याख्या की न्यायिक प्रक्रिया द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अदालत द्वारा लिए गए लाइन निर्णय की न्यायसंगतता हेज्ड है स्वयं लगाए गए न्यायिक प्रतिबंध द्वारा। यह हमारे संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो, संविधान के तहत दी गई शक्ति का एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा नहीं कर सकता है। इसके कार्य संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के दायरे में हैं। संविधान की व्याख्या में अंतिम मध्यस्थ के रूप में सर्वोच्च न्यायालय यह घोषित करता है कि कानून क्या है। उच्च न्यायपालिका को यह निर्धारित करने के लिए एक नाजुक कार्य सौंपा गया है कि संविधान ने सरकार की प्रत्येक शाखा को कौन सी शक्तियाँ प्रदान की हैं और क्या उस शाखा के कार्य इस प्रकार का उल्लंघन करते हैं सीमाएं, कानून बनाना सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और संविधान के

अंतिम व्याख्याकार के रूप में संवैधानिक सीमाओं को लागू करना संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए, न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा की संवैधानिकता की जांच करने के लिए विस्तारित होती है। यह एक नाजुक कार्य है, हालांकि यह राजनीतिक पहलुओं से भरा हुआ है, जिसे सावधानी और बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। उद्घोषणा की वैधता को अंतिम रूप से तय करने में, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायोचित और वैध होने पर कोई कठोर नियम या नियमों या सिद्धांतों का निश्चित सेट नहीं हो सकता है।

विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों पर न्यायिक समीक्षा से बचा जा सकता है, हालाँकि राजनीतिक प्रश्नों द्वारा छिपाए गए शुद्ध कानूनी प्रश्न हमेशा न्यायसंगत होते हैं। किसी विशेष विवाद पर निर्णय लेने के लिए अदालतों के पास न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक होने चाहिए। संवैधानिक योजना द्वारा बनाई गई राजनीतिक समन्वय कार्यकारी शाखा को व्यापक शर्तों में प्रदान की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि पर न्यायसंगतता न्यायिक समीक्षा का अभ्यास करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विचारों में से एक है। एक प्रारंभिक धारणा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियमित रूप से कार्य किए गए हैं।

न्यायिक समीक्षा का संबंध निर्णय की खूबियों से नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। यह इस आधार पर है कि आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली ने चुना है कि राजनीतिक जवाबदेही अन्य प्रकार की जवाबदेही से अधिक महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका अपनी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग तब कर सकती है जब उसे पता चलता है कि विवाद न्यायिक रूप से खोजे जाने योग्य और प्रबंधनीय मानकों पर आधारित नहीं है। . हालाँकि, यदि राजनीतिक मोटाई से छिपा हुआ कोई कानूनी प्रश्न उठता है, तो संवैधानिक न्यायालय की शक्ति और दरवाजे बंद नहीं होते हैं, न ही उन्हें विशेष रूप से राजनीतिक

मोटाई की आड़ में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, जब संविधान स्पष्ट रूप से ऐसा करता है। को इसका दायित्व सौंपा। राजनीतिक मोटाई का सिद्धांत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक प्रश्न का निर्णय करते समय न्यायालय को इस बात को सबसे आगे रखना चाहिए कि क्या न्यायालय के पास उसके समक्ष रखे गए विशेष विवाद का निर्णय करने के लिए न्यायिक रूप से खोज योग्य और प्रबंधनीय मानक हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि संविधान द्वारा एक समन्वित राजनीतिक विभाग को व्यक्तिपरक संतुष्टि व्यापक शब्दों में प्रदान की गई थी। अपने आप। यदि यह संतुष्ट है कि न्यायिक रूप से खोज योग्य और प्रबंधनीय मुद्दा उठता है, तो यह न्यायालय के लिए खोज आदेश जारी करने और मामले पर विचार करने और फिर नियम निसी जारी करने के लिए खुला हो सकता है। इस प्रकार यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि वह कानून को अपने आधार के रूप में निर्धारित करे और खोजे और संविधान द्वारा सौंपे गए अपने कर्तव्य में कानून को लागू करे, संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में, हालांकि यह एक नाजुक कार्य है और उचित घोषणा जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय समान रूप से सीमा की घोषणा और निर्धारण करता है और यह भी बताता है कि क्या कार्रवाई ऐसी सीमा का उल्लंघन है।"

16)**एस.एस. जयसिंघानी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर.** 1967[2], सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन आधिपत्य ने माना कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पूर्ण शक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके आधिपत्य ने देखा-

"इस संदर्भ में इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन की पहली अनिवार्यता है, जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था आधारित है।

[2] 1967 एस.सी. 1427

कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली में, विवेकाधिकार जब कार्यकारी अधिकारियों को दिया जाता है, तो अवश्य होना चाहिए स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर सीमित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कानून के शासन का मतलब है कि निर्णय ज्ञात सिद्धांतों और नियमों के आवेदन द्वारा किए जाने चाहिए और सामान्य तौर पर, ऐसे निर्णय पूर्वानुमानित होने चाहिए और नागरिक को पता होना चाहिए कि वह कहां है। बिना किसी सिद्धांत के या बिना किसी नियम के लिया गया निर्णय अप्रत्याशित होता है और ऐसा निर्णय कानून के शासन के अनुसार लिए गए निर्णय के विपरीत होता है। (देखें। डाइसी "संविधान का कानून" - दसवां संस्करण। परिचय पूर्व।) यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वंडरलिक, (1951-342 यूएस 98; 96बी लॉ ईडी 113) में डगलस, जे. ने कहा, "कानून अपने सर्वोत्तम क्षणों तक पहुंच गया है", "जब इसने मनुष्य को कुछ शासकों के अंतिम विवेक से मुक्त कर दिया है... .....जहाँ विवेक पूर्ण है वहाँ मनुष्य को हमेशा कष्ट सहना पड़ता है"। इसी अर्थ में कानून के शासन को सनक का कट्टर शत्रु कहा जा सकता है। विवेक, जैसा कि लॉर्ड मैन्सफील्ड ने कहा कि यह जॉन के मामले में क्लासिक शब्द है। विल्केस (1770-98 ईआर 327) "का अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित ठोस विवेक। इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, हास्य से नहीं, यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए।"

17)**ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य**[3]**,**1974, भगवती, जे. ने सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के लिए बोलते हुए घोषणा की कि प्रत्येक कार्रवाई जो मनमानी और अनुचित है उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत माना जाएगा।

[3] ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 555

18)वही दृष्टिकोण जो कई निर्णयों और कुमार श्री लेखा विद्यार्थी आदि बनाम यूपी राज्य और अन्य., 1991[4], उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर संपूर्ण केस कानून की समीक्षा करने के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"इस समय इस बात पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि भारत के संविधान की धारा 14 सरकारी नीति के मामलों पर भी लागू होती है और यदि सरकार की नीति या कोई कार्रवाई, यहां तक कि अनुबंध संबंधी मामले में भी, की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है।" तर्कसंगतता, यह असंवैधानिक होगा। (रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1628 और कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1992 देखें)। कर्नल ए.एस. सांगवान बनाम में भारत संघ, 1980 (सप्प) एससीसी 559, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1545 जबकि कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में नीति को बदलने की दिशा, जब क़ानून या नियम द्वारा बाधित नहीं की गई थी, को व्यापक माना गया था, इसे अनिवार्य माना गया था और संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है कि नीति में बदलाव निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए और यह आभास नहीं देना चाहिए कि यह मनमाने ढंग से या किसी गुप्त मानदंड से किया गया है। अनुच्छेद 14 का व्यापक दायरा और प्रत्येक राज्य की कार्रवाई की आवश्यकता इस कसौटी पर इसकी वैधता के लिए, राज्य की गतिविधि के क्षेत्र का अनादर, लंबे समय से तय किया गया है। इस न्यायालय के बाद के निर्णयों ने इस सिद्धांत की नींव को मजबूत किया है और इस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय के केवल दो हालिया निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।"

[4] ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 537

19)ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि हम अधिनियम की धारा 9(3)(i) की जांच करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि खंड (i) के तहत तीन व्यक्तियों को नामांकित करने की सरकार में निहित शक्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन है नामांकित किये जाने वाले व्यक्तियों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने पर निर्भर। इसलिए, यदि यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया है जिसके पास नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अभ्यास नहीं है, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग मनमानी और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा।

20)प्रश्न का दूसरा पहलू जिसकी जांच की आवश्यकता है वह यह है कि क्या निजी उत्तरदाता ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव है। दिनांक 20.2.1995 की अधिसूचना निजी उत्तरदाताओं की योग्यता के बारे में बात नहीं करती है। हालाँकि, खुद को संतुष्ट करने के लिए, क्या सरकार ने अधिनियम की धारा 9(3)(i) की आवश्यकताओं पर विचार किया और दो नगरपालिका समितियों में नामांकित करने से पहले निजी उत्तरदाताओं की योग्यता की जांच की, हमने संबंधित रिकॉर्ड के लिए भेजा। सरकार। हरियाणा के विद्वान उप महाधिवक्ता ने हमारे सामने एक फाइल पेश की है जिसमें अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत जारी की गई कई अधिसूचनाएं शामिल हैं। इनमें से दो अधिसूचनाएं 48 नगरपालिका समितियों से संबंधित हैं जिनमें बुरिया, तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर और पुन्हाना जिला गुड़गांव की नगरपालिका समितियां शामिल हैं। इस फ़ाइल में, हरियाणा के मुख्यमंत्री की 74 नगरपालिका समितियों में से प्रत्येक में तीन सदस्यों की नियुक्ति की इच्छा वाली एक सूची है। यह सूची उप प्रधान सचिव (सामान्य) द्वारा मुख्यमंत्री, हरियाणा को 17.2.1995 को भेजी गई है और सूची के नीचे एक नोट है "माननीय एम.एल.जी. से गुड़गांव में टेलीफोन पर बात की गई और उन्होंने आदेश दिया है

कि इस संबंध में आदेश दिए जाएं" उपरोक्त एम.सी.एस. को आज जारी किया जा सकता है सिवाय गुड़गांव, हिसार, करनाल और भिवानी जिले में आने वाली एम.सी.एस को छोड़कर, जिनके मामले में आदेश 24.2.1995 को जारी किए जाएंगे। फाइल में कुछ अन्य अधिसूचनाएं और श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री राजिंदर कुमार द्वारा दायर एक आवेदन शामिल है। स्वर्गीय राम सरूप को अपने पिता के नाम में सुधार के लिए। इस फ़ाइल में 1995 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 6226 में उत्तरदाताओं 3 से 5 और 1995 के 3874 में प्रतिवादी संख्या 3 की योग्यता दिखाने वाली कोई सामग्री नहीं है। इस फ़ाइल के अलावा, कोई भी सामग्री नहीं है हमारे सामने निजी उत्तरदाताओं के पास मौजूद योग्यताओं को दर्शाने वाली सामग्री प्रस्तुत की गई है। यहां तक कि निजी उत्तरदाताओं ने भी यह नहीं बताया है कि उनके पास क्या योग्यताएं हैं। उनमें से कोई भी यह कहने के लिए आगे नहीं आया है कि वह नगरपालिका का सदस्य बना हुआ है अतीत में समिति और इसलिए, नगरपालिका प्रशासन में अनुभव प्राप्त हुआ। उनमें से कोई भी यह नहीं कहता कि उसने नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई परीक्षा या प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है। उनमें से कोई भी यह नहीं कहता कि उसने स्थानीय स्वशासन में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है। उनमें से कोई भी यह दलील लेकर आगे नहीं आया कि उसके पास नगरपालिका कानूनों में विशेषज्ञता/विशेषज्ञता है या उसने नगरपालिका कानूनों से संबंधित मामलों को संभाला है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निजी उत्तरदाताओं में से किसी को भी नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान नहीं है और न ही उनके पास नगरपालिका प्रशासन में कोई अनुभव है और अपनी ओर से, सरकार ने उन्हें नगरपालिका समितियों में नामांकित करते समय अपने दिमाग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। . हमारे सामने रखी गई सामग्री से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों का कर्तव्य मुख्यमंत्री को सॉ की आवश्यकताओं के साथ-साथ नामांकित किए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव के बारे में सिखाना है, वे अपने कर्तव्य में पूरी तरह विफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप

उन व्यक्तियों को नामांकित किया गया जो कानून की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे।

21)संविधान के अनुच्छेद 243-आर और अधिनियम की धारा 9(3) का मूल उद्देश्य सरकार को कुछ ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने की शक्ति प्रदान करना है जो नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ना पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नगरपालिका समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है ताकि स्थानीय सरकार प्रशासन को नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र में उनके विशेष ज्ञान या अनुभव से लाभ मिल सके। यह वस्तु आक्षेपित अधिसूचना द्वारा पूरी तरह से विफल हो गई है।

22)ऊपर उल्लिखित कारणों से, हम दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं और सी.डब्ल्यू.पी. में उत्तरदाताओं 3 से 5 को नामांकित करने वाली अधिसूचना को रद्द करते हैं। 1995 का क्रमांक 6226 और सी.डब्लू.पी. में प्रतिवादी क्रमांक 3 1995 की संख्या 3874 क्रमशः नगरपालिका समिति, बुरिया, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर और नगरपालिका समिति, उहाना, जिला गुड़गांव क्रमश। ये उत्तरदाता अब से नगरपालिका समितियों के सदस्य नहीं रहेंगे। याचिकाकर्ताओं को दोनों याचिकाओं में 5,000/- रुपये की लागत मिलेगी।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा